

Regarding giving Special Status to Rajasthan

श्री अमरा राम (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यह सबसे ज्यादा डेजर्ट वाला प्रदेश है, जहां पानी की भयंकर कमी है। वहां पर मात्र एक प्रतिशत पानी है। आज आजादी के 75 सालों के बाद भी 80 प्रतिशत जनता, चाहे वह ग्रामीण जनता हो या शहरी जनता हो, वह आज भी शुद्ध पेयजल के लिए तरसती है। वहां पर फ्लोराइड युक्त पानी है, जिसके कारण वहां के लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ता है। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती है। राजस्थान वह प्रदेश है, जहां एक हजार किलोमीटर से ज्यादा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है।

आज वहां पर परिवहन की सबसे ज्यादा परेशानी है तथा शिक्षा और चिकित्सा की भी परेशानी है, क्योंकि आधी आबादी छितरी हुई, एक-एक खेत में बसी हुई है। अभी जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल देने का आह्वान किया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस योजना में सबसे पिछड़ा राजस्थान राज्य है। सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमकाथाना में पीने के पानी के लिए 7 हजार 900 करोड़ रुपये की एक योजना है, जिसमें केन्द्र और राज्य को 50-50 प्रतिशत पैसा देना है। केन्द्र सरकार ने पैसा दे दिया है, लेकिन राज्य अभी तक पैसा देने में सक्षम नहीं है। निश्चित रूप से राजस्थान के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि केन्द्र और राज्य की योजनाओं में 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र दे और 10 प्रतिशत पैसा राज्य दे।

आज राजस्थान एक-एक बूंद पानी के लिए तरसता है। राजस्थान के यमुना का हिस्सा आज तक राजस्थान को इन 75 सालों में नहीं मिला है।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को समाप्त कीजिए। आपका विषय आ चुका है।

श्री अमरा राम: सभापति महोदय, पोंग डैम में आज भी 0.7 मिलियन एकड़-फीट पानी, जो राजस्थान के हिस्से का है, वह उसे नहीं मिला है। चूँकि राजस्थान की जनता एक-एक बूंद पानी के लिए तरसती है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान को इस देश की सरकार स्पेशल कैटेगरी के राज्य का दर्जा दे। ?
(व्यवधान)